POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 01

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जनवरी, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राजस्थान में सत्ता पलट गई। सत्ता की बाजी कांग्रेस ने जीती। अशोक गहलोत मुख्य मंत्री और सचिन पायलट उप-मुख्यमंत्री बने हैं।

मुझे प्रसन्नता है, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 9 माह पूर्व कराया गया 'ग्रामगदर' जनमत सर्वेक्षण 2018 कई मायनों में खरा साबित हुआ है। तब करीब 58 फीसदी लोगों ने कांग्रेस की जीत का दावा किया था। यह ही नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में भी लोगों की पहली पसंद अशोक गहलोत थे।

मैं सर्वेक्षण में सहयोग देने वाले प्रदेश के सभी कार्यकताओं और 'ग्राम गदर' के पाठकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही प्रदेश में बनी नई सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प इत्यादि का उचित वातावरण बनाएं, जिससे कि रोजगार की तलाश में गांवों से पलायन की समस्या दूर हो।

मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सत्ता संभालते ही जनता से वादा किया है 'सरकार गुड गवर्नेंस देगी। किसानों के कर्जे माफ होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जन समस्याओं की सुनवाई होगी।' उन्होंने किसानों के कर्ज माफ कर एक वादा पूरा भी कर दिया है।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

मेरा मानना है, कर्ज माफी समस्या का अंत नहीं हैं। सरकार को किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए न केवल कृषि कल्याणकारी योजनाओं को सही रूप से धरातल पर उतारना होगा, बल्कि ऐसी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जिससे किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य मिले। सरकार को तेलंगाना प्रांत की तरह किसानों को एक निर्धारित राशि प्रति एकड़ देने की नीति अपनानी चाहिए।

मोबाइल व खातों को आधार से जोड़ने में चलेगी आपकी मनमर्जी

आधार नंबर को मोबाइल नंबरों और बैंक खातों से लिंक करने को वैधता प्रदान करने के लिए केंद्रीय केबिनेट ने दो मौजूदा कानूनों में संशोधन के विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह ऐच्छिक होगा यानी अनिवार्य नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट बैठक में टेलिग्राफ एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) में संशोधन के मसौदे को यह मंजूरी दी गई।

इस साल सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर अपने ऐतिहासिक फैसले में निजी कंपनियों द्वारा ऑनलाइन आधार प्रमाणिकरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद दूरसंचार कंपनियों ने सरकार से आधार के इस्तेमाल के प्रतिबंध से छूट की गुहार लगाई थी।

दोनों मौजूदा कानूनों में प्रस्तावित संशोधन हो जाने के बाद कोई व्यक्ति नए मोबाइल कनेक्शन लेने और बैंक खाता खोलने के लिए 12 अंक वाली पहचान संख्या को अपनी मर्जी से साझा कर सकेगा। इसी तरह पीएमएलए कानून में संशोधन के बाद लोगों के पास केवाईसी के लिए बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने का विकल्प होगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक केवल पैन कार्ड और सरकारी लाभ उठाए जाने की स्थिति में ही आधार लिंक की अनिवार्यता रहेगी। अब विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।

संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल पर 50 लाख का हर्जाना

सीकर जिले के खंडेला निवासी शिवदयाल पालीवाल ने राज्य उपभोक्ता आयोग में संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल के खिलाफ परिवाद दायर किया। उन्होंने परिवाद में आयोग को बताया कि उनके 30 वर्षीय पुत्र संजय को बुखार होने पर दुर्लभजी अस्पताल में दिखाया। यहां डॉ. अनुराग गोविल ने कई जांचें कराई पर इन सबकी रिपोर्ट सामान्य आई। संजय को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। इस बीच कई अन्य जांचें भी हुई लेकिन रिपोर्ट सामान्य बताई गई। कुछ दिन बाद ही संजय को सांस लेने में तकलीफ पैदा हो गई तो फेफड़े में संक्रमण बताकर आईसीयू में भर्ती कर लिया। उन्होंने बताया कि एण्डोस्कोपी के दौरान उनके पुत्र की श्वास नली में इंजरी हो गई, इससे खून फेफड़ों में चला गया।

मामले की सुनवाई पर आयोग ने माना कि एण्डोस्कोपी की रिपोर्ट किसी अन्य मरीज की थी, जिसे परिवादी के पुत्र की रिपोर्ट बताई गई। लापरवाही से संजय की मौत हुई है। आयोग ने संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल और डॉ. अनुराग गोविल को आदेश दिया कि वह संजय के माता-पिता को 50 लाख रुपए का हर्जाना और परिवाद की तारीख से हर्जाना राशि पर नौ फीसदी ब्याज अदा करें।

प्रदेश में किसानों के कर्ज हुए माफ

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी कर्जमाफी की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किसानों के दो लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। सहकारी बैंकों से लिए गए सभी अल्पकालीन ऋण माफ होंगे। इसके अलावा जो किसान राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण व अन्य बैंकों से लिया कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

किसानों को 30 नवम्बर 2018 तक लिए गए कर्ज पर यह राहत मिलेगी। भाजपा सरकार की ओर से माफ किए गए ऋण भी इसमें शामिल होंगे। कर्जमाफी का लाभ ले चुके वे किसान भी लाभान्वित होंगे जिनका कर्ज पचास हजार रुपए से अधिक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्ज माफी से सरकार के खजाने पर 18 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसमें भाजपा सरकार के समय माफ किए गए छह हजार करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

मीडिया सत्ता से सवाल पूछे

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग जनता से सीधे संपर्क में होते हैं। लिहाजा जनता के हित में मीडिया को सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने चाहिए। यह लोकतांत्रिक समाज की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने फर्जी खबरों को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जाता है।

पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि अफसरशाही विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसमें जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। नौकरशाही को विकास में योगदान के लिए अनुकूल बनाना होगा और कार्य में लचीलापन लाना होगा ताकि बेहतर नीतियां बनाई जा सकें।

केंद्रीय कृषि योजनाओं पर माथापच्ची

हाल ही हुए विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों में हुई भाजपा की हार के पीछे किसानों की नाराजगी को एक बड़ा कारण माना जा है। इसे देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय में सरकार की योजनाओं को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है।

कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को हिदायत दी है कि किसानों के कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। अधिकारियों से सभी राज्यों में किसान संबंधी योजनाओं में खर्च हुए धन का ब्योरा भी जुटाने को कहा गया है।

महिला सशक्तिकरण की जरूरत

प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला नीति बनाई हुई है। महिला आयोग भी बना हुआ है। सरकारी स्तर पर महिलाओं को

सशक्त बनाने की जरूरत भी महसूस की जाती रही है।

इन सबके बावजूद महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और इलाज की सुविधाएं, रोजगार की प्राथमिकता, पोषण के लिए गुणवत्तापूर्ण आहार, महिला अधिकारों की रक्षा, अपराधों पर नियंत्रण जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों के बावजूद ग्रामीण धरातल स्तर तक उनके सही लाभ नहीं मिल पा रहे। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि अब आशा के अनुरूप नई सरकार को इस दिशा में मजबूती से काम करने की जरूरत है।

हमारी सरकार गुड गवर्नेंस देगी

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पांच साल तक राजस्थान में कुशासन रहा है। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार गुड गवर्नेंस देगी। किसानों के कर्जे माफ होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जन समस्याओं की सुनवाई होगी।

उन्होंने कहा कुशासन के दौर में प्रदेश में रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो, आदिवासी क्षेत्रों में ब्रॉडगेज, हाडोती में डेम आदि योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। योजनाएं बंद होने से लोगों में भारी गुस्सा था। पांच साल में वसुंधरा राजे किसी से मिली ही नहीं। यहां तक कि जनता, विधायकों, मंत्रिमंडल के साथियों से भी नहीं मिलती थीं। एक गुस्सा था, उनके प्रति जो खुलकर सामने आया और अब कांग्रेस की सरकार बन रही है।

निःशुल्क दवा योजना में होगा सुधार

पिछली बार अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार निःशुल्क दवा योजना की जो सौगात देकर गई थी उसमें पांच सालों में बजट के अलावा कोई बदलाव नहीं आया। योजना में 600 से अधिक दवाइयां व शल्य उपकरण थे, वह आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

अब फिर से अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस योजना के गति पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और केंद्र की ओर से आयुष्मान भारत योजना भी लागू की जा चुकी है। अब प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पास तीनों योजनाओं के तालमेल की जिम्मेदारी है।

बच्चे हो रहे हैं कुपोषण के शिकार

अनेक सरकारी योजनाओं और मोटे खर्चे के बावजूद राज्य में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। कुपोषण दूर करने के लिए राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पोषाहार के साथ दूध पिलाने की योजना है। इन योजनाओं पर सालाना हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद धरातल पर सही परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं।

केंद्र सरकार के क्लिनीकल, मानवशास्त्रीय व बायो कैमिकल (सीएबी) सर्वे के अनुसार प्रदेश में 23 फीसदी बालक और 22.3 फीसदी बालिकाएं कुपोषण से ग्रसित हैं। पांच साल की आयु के 12.6 फीसदी बालक और 11.7 फीसदी बालिकाएं अतिकुपोषित हैं। पांच से 18 साल की आयु की 11.6 फीसदी लड़कियां व 17.2 फीसदी लड़के अतिकुपोषण के शिकार हैं।

जलवायु परिवर्तन से खेती पर संकट

भारत के 151 जिलों की फसलें, पेड़-पौधे और पशु जलवायु परिवर्तन के कारण अति संवेदनशील हालत में पहुंच चुके हैं। यह देश के कुल जिलों का करीब 20 फीसदी है।

कृषि मंत्रालय से जुड़े संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) की वार्षिक समीक्षा में यह चिंता जताई गई है। खेती पर जलवायु परिवर्तन का असर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि फसलों के उत्पादन के बारे में अनुमान भी गलत साबित हो रहे हैं।

हालांकि सरकार ऐसे कई कार्यक्रम चला रही है, जिससे खेती में हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। जलवायु परिवर्तन से न केवल तापमान बढ़ा है बल्कि बारिश भी कम हो रही है। इससे सिंचाई तंत्र भी खराब हुआ है।

घोषणा-पत्र पर हो अमल

चुनाव के ऐन मौके पर कांग्रेस ने घोषणा-पत्र जारी किया। इसमें किसानों का दस दिन में कर्ज माफ करने, युवाओं को रोजगार व बेरोजगारी भत्ता देने, गांवों के विकास को अहमियत देने, बच्चियों को मुफ्त शिक्षा, पंचायतों को अधिक अधिकार, जनता की भलाई और प्रदेश के विकास के बढ़-चढ़ कर वादे किए गए हैं।

अब नई सरकार को घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। सुशासन की दृष्टि से हर विधायक को अपने क्षेत्र के स्थानीय लोगों से भी उनकी जरूरतों और समस्याओं के बारे में समय-समय पर जानकारी लेना और उनका समाधान करना आवश्यक है। इससे प्रदेश के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता साबित हो सकेगी।

- रामजीलाल यादव, जयपुर

बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे लोग

प्रदेश में जनादेश कांग्रेस के पक्ष में गया है। इसमें सबसे बड़ा हाथ ग्रामीण मतदाताओं का रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने गांवों में अपने चुनाव प्रचार के दौरान शिक्षा, बिजली, पेयजल, सिंचाई, सड़क, चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतों और ग्रामीण विकास के मुद्दों को ज्यादा अहमियत दी और भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने में कमी नहीं रखी।

ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर लोगों ने सरकारी कामकाज की गति को कमजोर माना और बुनियादी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे। भाजपा सरकार ने सुधार के वादे तो किए पर ग्राम गदर जनमत सर्वेक्षण 2018 के अनुसार करीब 49 फीसदी लोगों ने वादों का क्रियान्वयन समय पर नहीं होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीण कहते हैं कि अब सारा दारोमदार मौजूदा सरकार पर है।

कैसे छुटकारा मिलेगा बेरोजगारी से

एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है। और यह आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार सृजन कम हुआ है। इसका कारण मैन्यूफेक्चरिंग, आईटी सैक्टर और मौजूदा उद्योगों का विस्तार नहीं होना है।

कौशल व आजीविका विकास के तहत युवाओं को भाजपा सरकार ने प्रशिक्षण तो दिया, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर विफल रही। गांवों में छोटे-लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धन्धों को खास अहमियत नहीं मिली। गैर-कृषि जैसे खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प आदि क्षेत्र में भी उचित वातावरण नहीं मिल पाया। रोजगार की तलाश में गांवों से लोग शहरों की तरफ भागने को विवश रहे।

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में बेरोजगारों को 3500 रुपए बेराजगारी भत्ता देने का वादा तो किया है, लेकिन इसका रोडमैप नहीं है। बेरोजगारों के स्थाई समाधान का कोई रास्ता भी तय नहीं है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कटूस' जयपुर